'राजस्थान को ऊर्जा के क्षेत्र में आत्म निर्भर बनाना चाहते हैं भजनलाल'

थर्मल एवं अक्षय ऊर्जा से 31825 मेगावाट बिजली उत्पादन की विभिन्न परियोजनाएं होंगी स्थापित

- इसके लिये 1.60 लाख करोड़ रूपए के निवेश का होगा करार
- साथ ही 10 मार्च को राज्य सरकार के विद्युत निगमों एवं केन्द्रीय उपक्रमों के मध्य 5 एमओयू एवं 1 पीपीए पर होंगे हस्ताक्षर
- एक और उपलब्धि होगी, राज्य सरकार एवं आरईसी के मध्य भी होगा एमओयू, परियोजनाओं के लिए मिलेगा 20 हजार करोड़ का ऋण

जयपुर। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की दूरगामी सोच एवं निरंतर प्रयासों से प्रदेश को ऊर्जा के क्षेत्र में अग्रणी एवं आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में 10 मार्च को नए कीर्तिमान स्थापित होंगे। प्रदेश में ऊर्जा प्रसारण तंत्र को सुदृढ़ बनाने एवं थर्मल व अक्षय ऊर्जा के उत्पादन की नई परियोजनाओं की स्थापना के लिए राज्य सरकार एवं केन्द्रीय उपक्रमों के मध्य विभिन्न एमओयू तथा पावर परचेज एग्रीमेंट होगा। राज्य में 31 हजार 825 मेगावाट से अधिक बिजली उत्पादन की विभिन्न परियोजनाओं सहित ऊर्जा क्षेत्र के विकास के लिए 1.60 लाख करोड़ रुपये के निवेश के लिए राज्य की 3 विद्युत निगमों एवं 6 केन्द्रीय उपक्रमों के उच्च अधिकारियों के मध्य रविवार सुबह मुख्यमंत्री कार्यालय में 5 एमओयू तथा एक पावर परचेज एग्रीमेंट किया जाएगा।

इन समझौतों के तहत 3325 मेगावाट क्षमता की थर्मल आधारित परियोजनाओं के लिए राजस्थान विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड (आरवीयूएन) के साथ कोल इंडिया लिमिटेड, राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम (एनटीपीसी) तथा एनएलसी इंडिया के मध्य एमओयू किया जाएगा। इसके अतिरिक्त अक्षय ऊर्जा आधारित 28 हजार 500 मेगावाट की परियोजनाओं के लिए आरवीयूएन तथा एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी के बीच एमओयू होगा। ये नई परियोजनाएं संयुक्त उद्यम के माध्यम से विकसित की जाएंगी तथा इन पर 1 लाख 50 हजार करोड़ रूपए का निवेश किया जाएगा। इसी प्रकार राज्य में विद्युत प्रसारण तंत्र को सुदृढ़ करने के लिए राजस्थान विद्युत प्रसारण निगम और पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन के बीच 10 हजार करोड़ रुपये के निवेश का समझौता होगा। साथ ही, 600 मेगावाट की सौर ऊर्जा परियोजनाओं के माध्यम से बिजली की आपूर्ति के लिए राजस्थान ऊर्जा विकास निगम एवं एसजेवीएन ग्रीन एनर्जी के बीच पावर परचेज एग्रीमेंट (पीपीए) भी किया जाएगा।

राजस्थान विद्युत उत्पादन निगम द्वारा छबड़ा तापीय विद्युत परियोजना में 1600 मेगावाट कोयला आधारित परियोजना के लिए एनटीपीसी के साथ तथा 25000 मेगावाट सौर/पवन परियोजना के लिए एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड के साथ समझौता किया जाएगा। इसके अतिरिक्त प्रदेश के अवसंरचना क्षेत्र के विकास के लिए राजस्थान सरकार के विभिन्न उपक्रमों को वित्तीय संसाधन उपलब्ध करवाने की दृष्टि से रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉर्पोरेशन (आरईसी) लिमिटेड एवं राज्य सरकार के मध्य भी एमओयू किया जाएगा। इसके अन्तर्गत आरईसी लिमिटेड राज्य सरकार के विभिन्न विभागों, उपक्रमों, संस्थाओं और योजनाओं के लिए 20 हजार करोड़ रूपए का ऋण प्रतिवर्ष उपलब्ध करवाएगा। इस एमओयू से आपणो अग्रणी राजस्थान की परिकल्पना साकार होगी और प्रदेश के अवसंरचना क्षेत्र जैसे बिजली, पानी, सिंचाई, मेट्रो, परिवहन एवं कृषि से सम्बंधित परियोजनाओं में तेजी से वृद्धि होगी जिससे राज्य आर्थिक दृष्टि से सम्पन्न प्रदेष बनने की ओर अग्रसर होगा।

राजस्थान पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन की ओर से 10 मार्च को सुबह छह बजे से दो दिन के लिये प्रदेशव्यापी हड़ताल का निर्णय लिया गया है। यह जानकारी एसोसिएशन के अध्यक्ष राजेन्द्र सिंह भाटी ने प्रेस विज्ञप्ति जारी कर दी। इस दौरान प्रदेश का कोई भी डीलर किसी भी प्रकार की खरीद व बिक्री नहीं करेगा।हड़ताल के निर्णय को देखते हुए शनिवार को शाम से ही जयपुर के पेट्रोल पंपों पर लोगों की भीड़ लगना शुरू हो गई।

कांस्टेबल के परिजनों को विशेष सहायता पैकेज

जयपुर। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने शुक्रवार को सिरोही के स्वरूपगंज थाना क्षेत्र के लौटाना गांव में महाशिवरात्रि पर्व पर हुए वारदात में पुलिस कांस्टेबल निरंजन सिंह की मृत्यु पर शोक प्रकट करते हुए घटना को दुर्भाग्यपूर्ण बताया है। मुख्यमंत्री ने कांस्टेबल निरंजन के एक आश्रित को सरकारी नौकरी सहित परिवार को विशेष आर्थिक सहायता पैकेज प्रदान करने की घोषणा की, जिसमें अन्य विभागीय परिलाभों सहित 1 करोड़ 35 लाख रुपए मृतक कांस्टेबल के परिवार को प्राप्त होंगे।

उन्होंने कर्तव्य निर्वहन के दौरान जान गंवाने वाले कांस्टेबल निरंजन सिंह को नमन किया और शोक संतप्त परिजनों के प्रति संवेदनाएं व्यक्त की। विशेष आर्थिक पैकेज में राज्य सरकार की ओर से मृतक आश्रित को उसके गृह जिले अथवा पदस्थापन क्षेत्र में एमआईजी श्रेणी का आवास, छात्रवृत्ति, बिजली कनेक्शन इत्यादि हेतु कुल 20 लाख रुपए की विशेष आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। इसके अतिरिक्त विभागीय प्रक्रियानुसार पारिवारिक पेंशन, राज्य बीमा, जीपीएफ, ग्रेच्युटी, सामूहिक व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा, विशेष जीवन बीमा, दयामूलक अनुदान नियमानुसार देय होंगे।

सिरोही जिले के पुलिस अधीक्षक अनिल कुमार ने बताया कि पुलिस द्वारा 7-8 व्यक्तियों को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। मुख्य आरोपी प्रवीण गरासिया की पहचान कर ली गई है, जिसकी गिरफ्तारी के प्रयास किए जा रहे हैं। मूल रूप से गोटन (नागौर) के निवासी मृतक पुलिस कांस्टेबल निरंजन सिंह 3 वर्षों से स्वरूपगंज में पदस्थापित थे।